बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

ल.अं./50/एसएलबीसी/मार्च 2024/88 31.05.2024

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0) के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय,

विषय :- **राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ.प्र.) की मार्च 2024 त्रैमासांत की बैठक दिनांक 28.05.2024 का कार्यवृत्त**

कृपया दिनांक **28.05.2024** को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की गरिमामयी उपस्थिति में सम्पन्न राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ.प्र.) की मार्च 2024 को समाप्त तिमाही की समीक्षा बैठक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त एवं कार्यवाही बिन्दु आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय,

(समीर रंजन पंडा)
महाप्रबन्धक एवं संयोजक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.)

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.), अंचल कार्यालय, लखनऊ अंचल, "बड़ौदा हाउस", वी–23, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010
State Level Bankers' Committee (U.P.), Zonal Office, Lucknow Zone, "Baroda House", V-23, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
फोन / Phone : 0522-6677607 (GM), 6677609 (Sectt.), 6677722 (DGM), 6677730 (CM), 6677721, 6677725
ई–मेल / E-mail : slbc.up@bankofbaroda.com, वेबसाइट / Website : www.slbcup.com

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की मार्च 2024 तिमाही की बैठक दिनांक 28.05.2024 का कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) की मार्च 2024 त्रैमासिक समीक्षा बैठक दिनांक 28.05.2024 को "मुख्य सचिव सभागार", लोक भवन, हजरतगंज, लखनऊ में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्री लाल सिंह, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी।

बैठक में श्री दुर्गा शंकर मिश्र, आई.ए.एस., मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन; श्री देवेश चतुर्वेदी, आई.ए.एस., अपर मुख्य सचिव, कृषि, उ.प्र. शासन; श्री दीपक कुमार, आई.ए.एस., अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ.प्र. शासन; श्री आलोक कुमार, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव, एम.एस.एम.ई., उ.प्र. शासन; श्री आलोक कुमार, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव, नियोजन, उ.प्र. शासन; श्री पंकज कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ; श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त ,बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ. प्र.; श्री संजय कुमार डोरा, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, लखनऊ; श्री मनीष सिन्हा, महाप्रबंधक, सिडबी, लखनऊ श्री समीर रंजन पंडा, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, एस.एल.बी.सी. (उ.प्र.); श्री आनंद बिक्रम, महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारीगणों द्वारा सहभागिता की गई| बैठक में भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 21.02.2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि
Confirmation of Minutes of Last SLBC Meeting dated 21.02.2024

दिसंबर 2023 त्रैमासिक की बैठक दिनांक 21.02.2024 के कार्यबिन्दु एवं कार्यवृत्त सभी सदस्यों को एस.एल.बी.सी. के पत्रांक ल.अं./50/एस.एल.बी.सी./45 दिनांक 07.03.2024 के माध्यम से प्रेषित किये गये थे, जिसकी पुष्टि समिति द्वारा की गयी।

बैठक के प्रारम्भ में **श्री समीर रंजन पंडा, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0)** ने सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए प्रदेश में गत तिमाही के दौरान घटित महत्वपूर्ण बैंकिंग गतिविधियों के अंतर्गत प्रदेश की स्थिति पर प्रकाश डाला:

- मार्च 2024 में प्रदेश के जमा एवं अग्रिम में 13% एवं 22% की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई है परंतु प्रदेश का आधारभूत जमा अधिक होने के कारण ऋण जमानुपात में आशातीत वृद्धि अपेक्षित है| प्रदेश का ऋण जमानुपात मार्च 2023 के स्तर 54.54% से बढ़कर मार्च 2024 में 58.72% पहुंच गया है तथा समस्त बैंकर्स प्रदेश के ऋण जमानुपात को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने हेतु सतत प्रयासरत है|
- वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत मार्च 2024 में 111.12% की उपलब्धि हासिल की गई जो प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक है| एम एस एम ई के अंतर्गत 202% की अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की गई है| उन्होंने बैंको द्वारा प्रदान किए जा रहे सहयोग किए लिए धन्यवाद ज्ञापित किया|
- आज प्रदेश के सभी 75 जनपदों द्वारा तैयार समेंकित वार्षिक ऋण योजना 2024- 25 का विमोचन प्रस्तावित है।
- वित्तीय वर्ष 2024- 25 हेतु तैयार वार्षिक ऋण योजना में विगत वर्ष के लक्ष्य के सापेक्ष 48% से अधिक की वृद्धि निर्धारित की गई है| इस लक्ष्य की शत प्रतिशत उपलब्धि हेतु रणनीति बनाते हुए सघन प्रयास प्रारम्भ किए जाने हेतु सभी बैंकर्स साथियों से आह्वान किया|

- केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न प्रायोजित योजनाएं PM Surya Ghar Yojana, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, PM Vishwakarma Yojana, PM Swamitva Yojana etc में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए अधिक से अधिक ऋण प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध दोहराया|

अंत में उन्होंने मुख्य सचिव महोदय को उनके अमूल्य समय प्रदान करने हेतु हृदय से आभार व्यक्त किया।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में उपस्थित श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, आई.ए.एस., मुख्य सचिव, उ. प्र. शासन; केन्द्र व राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं विभिन्न बैंको के वरिष्ठ कार्यपालक गणों का अभिवादन करते हुए **श्री लाल सिंह, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा** ने अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में वैश्विक, राष्ट्रीय एवं प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों तथा प्रदेश में सम्पन्न विभिन्न कार्यक्रमों से समिति को निम्नवत अवगत कराया :

- देश के आर्थिक परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मार्च 2024 में Trade Deficit US$ 78.1 bn रहा तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश की GDP Growth 6.8% रहने का अनुमान है|
- प्रदेश विकास के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है| देश की GDP में हमारा प्रदेश 9.20% की हिस्सेदारी के साथ द्वितीय स्थान पर है|
- प्रदेश में कृषि क्षेत्र में असीम संभावनाएं व्याप्त हैं एवं सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिचाई योजना, ड्रोन आधारित निगरानी एवं फसल सुरक्षा योजनाओं के साथ साथ खाद प्रसंस्करण, भण्डारण तथा कोल्ड चेन मैनेजमेंट के क्षेत्र पर भी विशेष ज़ोर दिया जा रहा है|
- गत 7 वर्षो में प्रदेश का कुल जमा एवं अग्रिम क्रमश: दो गुना और ढाई गुने से अधिक हो गया है| कुल व्यवसाय वर्ष 2017 के रू 12.80 लाख करोड़ से बढ़कर रू 27.97 लाख करोड़ पहुंच चुका है|
- प्रदेश सरकार एवं सभी बैंकर्स के सम्मिलित प्रयासों से प्रदेश के ऋण प्रवाह में बढ़ोत्तरी हुई है तथा मार्च 2024 में ऋण जमानुपात 58.72% के स्तर पर पहुंच गया है|
- बैंकिंग सेवाओं को विस्तार देने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए "ONE GP ONE BC" कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य 58,000 बी सी सखियों के सापेक्ष 38000 से अधिक बी सी सखियों को ऑनबोर्ड किया जा चुका है|
- मार्च 2023 में बैंकिंग आउटलेट्स की संख्या 2,01,587 थी जो 1,12,355 बैंकिंग आउटलेट्स (55.73%) की वृद्धि के साथ मार्च 2024 में बढ़कर 3,13,942 बैंकिंग आउटलेट्स पहुंच गई है|
- प्रधानमंत्री जन धन योजनांतर्गत मार्च 2024 तक 9.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं जो मार्च 2023 में खोले गए कुल 8.67 करोड़ खातों से 0.58 करोड़ अधिक है|
- जन सुरक्षा योजनाओं यथा PMJJBY & PMSBY के अंतर्गत मार्च 2024 में क्रमश: 2.12 करोड़ एवं 6.09 करोड़ नामांकन करते हुए हमारा प्रदेश दोनों योजनाओं में पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर रहा|
- अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अभी तक 103 लाख नामांकन किए जा चुके हैं| वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु आवंटित लक्ष्य 15.83 लाख के सापेक्ष मार्च 2024 तक 21.49 लाख (135%) नामांकन किए गए हैं| वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु नोडल एजेंसी - PFRDA द्वारा प्रदेश को "Ultimate Leadership Award" के लिए नामित किया गया है|
- डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत बैंको द्वारा मार्च 2024 तक कुल 893 करोड़ से अधिक ट्रांजेक्शंस किए जा चुके हैं|
- वार्षिक ऋण योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में लक्ष्य रू 3.48 लाख करोड़ के सापेक्ष रू 3.87 लाख करोड़ (111%) की उपलब्धि दर्ज की गई|
- मार्च 2024 तक एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के अंतर्गत कुल रू 203834 करोड़ (202%) का ऋण वितरण किया गया जो गत वर्ष की समान अवधि की उपलब्धि (रू 150032 करोड़) से रू 53802 करोड़ अधिक है| प्रदेश सरकार द्वारा एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाने हेतु किए गए प्रयासों से ही हमारा प्रदेश एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है|

- वर्तमान परिपेक्ष्य में हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश से एम.एस.एम.ई. प्रधान प्रदेश की ओर अग्रसर हो रहा है| वार्षिक ऋण योजना 2024-25 में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्यों को विगत वर्ष के सापेक्ष डेढ़ गुना अधिक निर्धारित किया गया है| उन्होने प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि नई योजनाओं, MSME clusters आदि के माध्यम से नई संभावनाओ का सृजन किया जाये|

- भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही पी एम स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रदेश में अत्यधिक सम्भावनाएं व्याप्त हैं एवं इसके क्रियान्वयन (implementation) में तेजी लाने की आवश्यकता है ताकि प्रदेश के ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्रों में ऋण प्रवाह (credit flow) को बढ़ाया जा सके जिससे प्रदेश के ऋण जमा अनुपात में वृद्धि की जा सके |

- सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत जिलाधिकारी स्तर पर लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण में हमें प्रदेश सरकार से सहयोग प्राप्त होता रहा है|

- नीति आयोग ने देशभर के 112 पिछड़े जनपदों को चिन्हित किया है जिसमें हमारे प्रदेश के 8 जनपद यथा बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर एवं सोनभद्र शामिल हैं| आयोग द्वारा निर्धारित 6 संकेतको पर अच्छा कार्य हो रहा है परन्तु MUDRA योजना में अभी सभी बैंकों को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है|

अंत में उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किये जा रहे सहयोग हेतु धन्यवाद दिया जिनके द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों एवं मज़बूत कानून व्यवस्था के फलस्वरूप प्रदेश के अर्थिक परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है जो सभी बैंकों की व्यावसायिक प्रगति में भी परिलक्षित होता है|

श्री पंकज कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ ने अपने संबोधन में मुख्य सचिव महोदय का अभिवादन करते हुए सभा में उपस्थित प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों सहित समस्त बैंको व अन्य वित्तीय संस्थानों के अधिकारीगणों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए सभा को निम्न बिन्दुओं से अवगत कराया :

- TReDS पर चर्चा करते हुए कहा कि अभी तक प्रदेश सरकार का केवल एक ही Institution ऑनबोर्ड हुआ है| उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि अति शीघ्र प्रदेश सरकार की सभी कंपनियों को TReDS पर ऑनबोर्ड कराया जाये|
- प्रदेश का ऋण जमानुपात मार्च 2023 के स्तर 54.54% में 4.18% की वृद्धि करते हुए मार्च 2024 में 58.72% के स्तर पर पहुंच गया है| साथ ही उन्होंने 9 जनपद, जिनका ऋण जमानुपात 40% से कम है, में विशेष ध्यान देते हुए ऋण प्रवाह बढ़ाये जाने हेतु संबन्धित बैंको से आह्वान किया।

(कार्यवाही: संबन्धित बैंक)

- Deepening of Digital Payments Ecosystem कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों को 100% Digitized किए जाने हेतु अग्रणी बैंको से अनुरोध किया कि अग्रणी जिला प्रबन्धक के माध्यम से बैंको का अनुश्रवण करते हुए यथाशीघ्र संतृप्त कराना सुनिश्चित करें| साथ ही उन्होंने Digital संतृप्तीकरण हेतु अधिक वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन करने पर बल दिया|

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ने मुख्य सचिव महोदय का एस.एल.बी.सी. की बैठक के आयोजन हेतु अपना बहुमूल्य समय देने हेतु धन्यवाद देते हुए अपने सम्बोधन में निम्न बिदुओं को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया :-

- प्रदेश के ऋण जमानुपात में गत वर्ष (मार्च 2023) के सापेक्ष 4.18% की वृद्धि करते हुए मार्च 2024 में 58.72% के स्तर पर पहुंच गया है|

- 40% से कम ऋण जमानुपात वाले जनपदों की संख्या मार्च 2023 के स्तर (13 जनपद) से घटकर मार्च 2024 में 9 जनपद हो गई है|

- वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत मार्च 2023 की उपलब्धि (102%) की भांति मार्च 2024 में भी आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष 111% की उपलब्धि दर्ज की गई है|

- प्रदेश में वार्षिक ऋण योजना 2024-25 हेतु रू 5.18 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लक्ष्य रू 3.48 लाख करोड़ में रू 1.70 लाख करोड़ की वृद्धि दर्शाता है| उन्होंने वार्षिक ऋण योजना 2024-25 हेतु आवंटित लक्ष्यों को हासिल किए जाने हेतु समस्त बैंको से आह्वान किया।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

- PM SVANidhi योजना के अंतर्गत लंबित समस्त आवेदन पत्रों का त्वरित गति से निस्तारण करने एवं स्ट्रीट वेंडर्स को Digitally Onboard किए जाने हेतु समस्त बैंको से आह्वान किया|

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

- स्वयं सहायता समूह को क्रेडिट लिंकेज प्रदान किए जाने में बैंको द्वारा बेहतरीन प्रयास किए गए है| क्रेडिट लिंकेज हेतु लंबित समस्त आवेदन पत्रों में आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु समस्त बैंको से आह्वान किया |

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

श्री संजय कुमार डोरा, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ ने सभा में उपस्थित समस्त अथितियों का अभिवादन करते हुए निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला:

- सर्वप्रथम वित्तीय वर्ष 2023-24 में वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत आवंटित लक्ष्यों को शत प्रतिशत हासिल करने हेतु समस्त Stakeholders को बधाई दी|

- वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत अन्य सेक्टर यथा Export, Housing, Education, Social Infrastructure जो कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, के अंतर्गत 42% की उपलब्धि हासिल की गई है| इन क्षेत्रों में ऋण बढ़ाने हेतु समस्त बैंको से आह्वान किया|

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

- वार्षिक ऋण योजना 2023-24 के कृषि क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्यों के सापेक्ष 79% की उपलब्धि दर्ज किए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि लगभग 60% आबादी कृषि और कृषि संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर है। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों यथा पूर्वी उ.प्र., बुन्देलखण्ड के साथ साथ संभावनाशील जनपदों में पश्चिमी उ. प्र. के जनपदों की तुलना में कम ऋण प्रवाह पर ध्यान आकृष्ट करते हुए समान ऋण प्रवाह प्रदान किए जाने पर जोर दिया गया।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदेश के ऋण जमानुपात में लगभग 4.18% की वृद्धि हुई है| प्रदेश का ऋण जमानुपात राष्ट्रीय स्तर (78%) से काफी कम है जिसे 65% तक पहुंचाने हेतु एक उपसमिति का गठन किया जाना आवश्यक है|

श्री आलोक कुमार, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव, एम.एस.एम.ई., उ. प्र. शासन ने सभा को निम्न बिन्दुओं से अवगत कराया :

- केंद्र सरकार की योजना - RAMP (Raising and Accelerating MSME Productivity) की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए बताया कि एम.एस.एम.ई. ईकाईयां जो 3 करोड़ से 5 करोड़ का टर्नओवर कर रही हैं उनको 50 करोड़, 100

करोड़, 500 करोड़ का ऋण प्रदान किया जाये साथ ही ऐसे कम से कम 1000 Model ईकाई स्थापित किए जाये|

(कार्यवाही: सम्बन्धित बैंक)

श्री आलोक कुमार, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव, नियोजन, उ. प्र. शासन ने सभा को निम्न बिन्दुओं से अवगत कराया :

- वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश का Incremental CD Ratio 91% रहने की सराहना करते हुए बताया कि यह इस बात का द्योतक है कि प्रदेश में निरंतर ऋण प्रवाह में वृद्धि हुई है परंतु प्रदेश का ऋण जमानुपात अभी भी राष्ट्रीय औसत से काफी कम है जिस पर और अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है|
- वर्ष 2027 तक प्रदेश को 1 $ ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने हेतु प्रदेश में ऋण प्रवाह तथा ऋण जमानुपात बढ़ाने पर बल दिया|

श्री पवन कुमार, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, साइबर क्राइम, लखनऊ ने अपने सम्बोधन में प्रदेश में हो रहे साइबर क्राइम पर प्रकाश डालते हुए समस्त बैंको से 24X7 कंट्रोल रूम/ नोडल ऑफिसर नामित किए जाने हेतु आह्वान किया| साथ ही बैंक शाखाओं में खोले जाने वाले खातों में पूर्ण KYC & Due Diligence किया जाना सुनश्चित करे| साथ ही सभी Banking Transactions की भी सतत निगरानी करें जिससे Banking System के द्वारा Money Mule transactions न हो|

(कार्यवाही: सम्बन्धित बैंक)

श्री देवेश चतुर्वेदी, आई.ए.एस., अपर मुख्य सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने सम्बोधन में अपने विभाग से सम्बन्धित निम्न बिन्दुओं को सभा के समक्ष रखा :

- फसल बीमा योजना के अंतर्गत कृषकों का आच्छादन कुल प्रदान किए जा रहे किसान क्रेडिट कार्डो से काफी कम है जिससे प्रदेश के कृषकों को योजना का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है| उन्होंने समस्त बैंको से आह्वान किया कि योजनांतर्गत पात्र अधिकाधिक कृषकों को आच्छादित कराते हुए योजना का लाभ प्रदान करने का कष्ट करें|

(कार्यवाही: सम्बन्धित बैंक एवं इंश्योरेंस कंपनी)

- कृषि उत्पादक संगठनो को त्वरित गति से ऋण सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है जिससे कृषि अवस्थापना सुविधाओं का विकास त्वरित गति से किया जा सके|
- पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थापना सुविधाओं को विकसित किए जाने की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं| कृषि क्षेत्र में मियादी ऋण (Term Lending) को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है|

सभी गणमान्य अतिथियों के सम्बोधन के पश्चात सभा के समक्ष पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति दी गयी जिसके माध्यम से विस्तृत रूप से विभिन्न एजेंडा बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

श्री दुर्गा शंकर मिश्र, आई.ए.एस., मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने संबोधन में सभा में उपस्थित प्रदेश सरकार एवं बैंको के वरिष्ठ अधिकारीगणों को समीक्षा बैठक में निम्नवत संबोधित किया :

- सर्वप्रथम उन्होंने प्रदेश के ऋण जमानुपात में मार्च 2023 के स्तर में 4.18 % की वृद्धि कर मार्च 2024 में 58.72% पहुंचाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए समस्त बैंको को बधाई दी| साथ ही मार्च 2025 में ऋण जमानुपात को 67% के स्तर तक पहुंचाने हेतु समस्त बैंको को निर्देशित किया|

(कार्यवाही: सम्बन्धित बैंक)

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदेश के 9 जनपदों, जिनका ऋण जमानुपात 40% से कम है, में विशेष कार्ययोजना बनाते हुए उप समिति का गठन कर एक विशेष एस.एल.बी.सी. बैठक किए जाने हेतु निर्देशित किया| साथ ही मार्च 2025 तक इन जनपदों के ऋण जमानुपात में 7% की वृद्धि किए जाने हेतु निर्देशित किया|

(कार्यवाही: संबन्धित अग्रणी बैंक, एस.एल.बी.सी. विभाग एवं संस्थागत वित्त विभाग)

- प्रदेश के ऋण जमानुपात को राष्ट्रीय औसत तक पहुंचाने हेतु बैंको को विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है तथा प्रदेश में स्थापित की जा रही विभिन्न औद्योगिक ईकाईयों को प्रदेश में स्थित बैंको द्वारा ऋण सुविधा प्रदान किए जाने के निर्देश दिये|

(कार्यवाही: सम्बन्धित बैंक)

- प्रदेश में कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं व्याप्त है| प्रदेश में कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को और बढ़ाने हेतु एक उप समिति का गठन किए जाने हेतु निर्देशित किया जिसकी बैठकों में एक रणनीति बनाते हुए विभिन्न मानको पर चर्चा की जाये|

(कार्यवाही: एस.एल.बी.सी. विभाग एवं संस्थागत वित्त विभाग)

- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई ONE GP ONE BC SAKHI योजना के अंतर्गत 50000 बी सी सखियों के लक्ष्य के सापेक्ष प्रदेश में 38660 बी सी सखियो को ऑनबोर्ड किया जा चुका है| उन्होंने शीघ्र शेष बी सी सखियों को ऑनबोर्ड किए जाने हेतु निर्देशित किया|

(कार्यवाही: सम्बन्धित पार्टनर एजेंसी)

- कृषि क्षेत्र एवं एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की Recycling किए जाने हेतु अनुरोध किया|

(कार्यवाही: सम्बन्धित बैंक)

- उन्होंने भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पी.एम. विश्वकर्मा योजना एवं पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने हेतु निर्देशित किया ताकि आमजनमानस तक इन योजनाओ का लाभ पहुंच सके|

(कार्यवाही: सम्बन्धित बैंक)

- उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक से कहा कि TReDS के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु पूर्व की भांति workshop कराई जाये ताकि सभी संबन्धित संस्थाओं को इसके प्रति जागरूक किया जा सके|

(कार्यवाही: भारतीय रिजर्व बैंक)

- डिजिटल ट्रांजेक्शंस को बढ़ावा देने हेतु Physical/ Virtual Mode में Financial Literacy Camps का आयोजन किए जाने हेतु निर्देशित किया|

- प्रदेश सरकार द्वारा आगामी समय में शुरू की जाने वाली मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कर युवकों को योजना का लाभ प्रदान किए जाने हेतु निर्देशित किया|

(कार्यवाही: सम्बन्धित बैंक)

- प्रदेश के जनपद फ़रूखाबाद में पायलट आधार पर कृषकों को 15 मिनट में ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जा रहा है जिसे अन्य जनपदों में भी लागू किए जाने की आवश्यकता है|

अंत में उन्होंने एक बार पुन: प्रदेश में बैंको द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए समीक्षा बैठक में प्रतिभाग करने हेतु सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया|

बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई |

****